

My Notes.....

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष में महाशक्ति बना भारत

भारत ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से ऐंटी-सैटलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। यह डीआरडीओ की ओर से एक तरह का तकनीकी मिशन था। मिसाइल के परीक्षण के लिए जिस सैटलाइट को निशाना बनाया गया, वह भारत के उन उपग्रहों में से है, जो पहले ही पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद हैं। इसे 'मिशन शक्ति' नाम दिया गया है। इस परीक्षण के तहत डीआरडीओ ने अपने सभी तय लक्ष्यों को हासिल किया। भारत ने मिशन शक्ति द्वारा 300 किमी दूर अंतरिक्ष में सैटलाइट को भेदा है। भारत ने इस मिशन को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के जरिए अंजाम दिया। ऐंटी सैटलाइट मिसाइल भी स्वदेश निर्मित ही था। इस परीक्षण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में ताकत के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो गया है।

क्या है

1. इस मिशन में पूरी तरह से भारत में तैयार ऐंटी-सैटलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसमें डीआरडीओ के बैलिस्टिक बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया था।
2. इस परीक्षण से पैदा हुआ मलबा आने वाले कुछ सप्ताह में धरती पर गिरेगा, यह आसमान में नहीं फैलेगा। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा।
3. भारत लंबे समय से स्पेस में सफलताएं हासिल कर रहा है। बीते 5 सालों में यह रफतार और तेज हुई है। मंगलयान मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसके बाद सरकार ने गगनयान मिशन को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस परीक्षण की सफलता को लेकर पूरी तरह विश्वस्त होने के बाद ही इसे अंजाम दिया।
4. भारत का बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई संधि सैटलाइट भारतीय अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश न कर सके। इससे दुश्मन देशों के लिए भारत की जासूसी करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत के संसाधनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
5. भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों का यह परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं किसी देश के खिलाफ नहीं हैं और न ही इनका कोई सामरिक उद्देश्य है।



लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट क्या होते हैं

1. लो-अर्थ ऑर्बिट LEO सैटलाइट सिस्टम का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। ये सैटलाइट्स पृथ्वी की सतह से 650-1,600 किलोमीटर ऊपर होते हैं।
2. इन सैटलाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से ई-मेल, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पेजिंग जैसे डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। ये सैटलाइट बहुत तेजी से परिभ्रमण मूव करते हैं और इन्हें स्पेस में स्थिर फिक्स नहीं किया जाता है। ज्यादातर कम्युनिकेशन ऐप्लीकेशंस लो-अर्थ ऑर्बिट LEO सैटलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लो-अर्थ ऑर्बिट में इन सैटलाइट को स्थापित प्लेस करने में कम एनर्जी लगती है। इसके अलावा, सफल ट्रांसमिशन के लिए इन सैटलाइट्स को कम पावरफुल ऐम्प्लिफायर की जरूरत होती है।

3. लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट की हाई स्पीड के कारण इन सैटलाइट से ट्रांसमिट होने वाला डेटा एक सैटलाइट से दूसरे में जाता है, क्योंकि सैटलाइट बहुत तेजी से ट्रांसमिशन स्टेशन की परिधि रेंज में आते-जाते रहते हैं। लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट को लगातार संकेत कवरेज उपलब्ध कराना होता है।
4. स्टडी जानकारी में खुलासा किया गया है कि इन सैटलाइट्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लो-अर्थ ऑर्बिट में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ऑर्बिट में सैटलाइट्स की संख्या को लगातार ट्रैक करती है।

सैटलाइट्स की कैटिगरी के प्रकार

1. सैटलाइट्स की तीन प्रकार कैटिगरी होते होती है। लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट और जियो सैटलाइट।
2. लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट, जियो सैटलाइट के मुकाबले छोटे होते हैं। लो-अर्थ ऑर्बिट सैटलाइट में नई टेक्नॉलजी और तथ्य , कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक होता है।
3. हालांकि, किसी सेलेक्टेड लोकेशन में वांछित फुल कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए 1,000 से ज्यादा लो-ऑर्बिट सैटलाइट्स की जरूरत पड़ सकती है।

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) सफलतापूर्वक सम्पन्न न हुई। कार्यशाला में 33 देशों के विकास और आपदा जोखिम विशेषज्ञ, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य भागीदारों ने भाग लिया। कार्यशाला में अपने विशेष संबोधन में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह ने जन-केंद्रित समाधान पाने के लिए सहनशील आधारभूत ढांचे पर सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया।

क्या है

1. कार्यशाला में प्रमुख आधारभूत ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और पेयजल आदि में आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की गई।
2. इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकृति आधारित नवाचार और इसके आधारभूत ढांचे के सृजन, संचालन और रखरखाव में प्रभाव पर भी चर्चा की गई।
3. कार्यशाला के दौरान आधारभूत ढांचे के लिए वित्त और बीमा संबंधी प्रायोगिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसमें आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे के लिए प्रस्तावित गठबंधन (सीडीआरआई) को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत का मंच तैयार हुआ।
4. सीडीआरआई की परिकल्पना, सूचना के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण भागीदारी के रूप में की गई है। भारत ने नई दिल्ली में 2016 में आयोजित एशियन आपदा जोखिम कम करने पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तुरंत बाद सीडीआरआई के सृजन की घोषणा की थी।
5. दूसरे आरडब्ल्यूडीआरआई का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने संबंधी कार्यालय और ग्लोबल कमीशन ऑन एडोप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा किया गया।

नीति आयोग फिनटेक कॉन्क्लेव 2019

नीति आयोग 25 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर नगर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में एक दिनभर चलने वाले फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत के फिनटेक क्षेत्र में बढ़ती उंचाइयों को आकार देना, भविष्य की रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों के लिए योजना बनाना तथा व्यापक वित्तीय व्यापक वित्तीय समावेश के लिए कदमों पर विचार करना है। इस कॉन्क्लेव में वित्तीय केंद्रीय मंत्रालयों, में वित्तीय स्थान- केन्द्रीय मंत्रालयों, विनियामकों, बैंकों, स्टार्टअप्स, सेवा प्रदाताओं एवं उद्यमियों के प्रतिनिधियों ने उद्यमियों के प्रतिनिधि भाग लिए।

क्या है

1. इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करेंगे तथा इसमें सचिव (वित्तीय मामले विभाग), सचिव (वित्तीय सेवा विभाग), अध्यक्ष (सेबी), सचिव (एमईआईटीवाई), सचिव (राजस्व विभाग), सचिव (एमएसएमई), भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इत्यादि भाग लेंगे। इत्यादि भाग लिए।
2. यह कॉन्क्लेव एचडीएफसी बैंक, इंडसइन्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, टाटा कैपिटल सहित प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं बैंक बाजार, फोन पे, कैपिटल फ्लोट, जेरोधा, पेटीएम, मोबिक विक, पे यू सहित फिनटेक एवं अग्रणी वैचर कैपिटल निवेशक, राज्य सरकारें एमएसएमई एवं उद्योग के इन विषयों के विशेषज्ञों के तीन सौ से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी की।
3. कॉन्क्लेव के समापन सत्र में वित्तीय समावेश के ग्राहक/व्यापारी की डिजिटल ऑन बोर्डिंग, मिलेनियल इंडिया के लिए वित्तीय उत्पादों का निर्माण, फिनटेक के उभरते क्षेत्र, फिनटेक उद्योग में निवेश में तेजी लाने तथा एमएसएमई का वित्तीय समावेश जैसे विषयों पर विभिन्न पैनलों के क्षेत्र-विशिष्ट निष्कर्षों के समेकन पर प्रस्तुतियां शामिल हुई।
4. डिजिटल इंडिया एवं वित्तीय समावेश के लिए स्वैच्छिक आधार सहित भारतीय अनेकता के विकास पर केन्द्रित भारत सरकार के प्रयासों के कारण वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के मन में उल्लेखनीय दिलचस्पी पैदा हुई है।

पृष्ठभूमि

1. भारत वैश्विक रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है और इस उद्योग के अनुसंधानों ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर या खुदरा तथा एसएलई ऋण का 60 प्रतिशत डिजिटल तरीके से वितरित तरीके से सवितरित हो जाएगा।
2. भारतीय फिनटेक प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है जिसने 2014 से लगभग छह बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है।
3. भारतीय फिनटेक उद्योग उन्नत जोखिम प्रबंधन एवं कृत्रिम आसूचना में अत्याधुनिक बौद्धिक सम्पदा परिसंपतियों का सृजन कर रहा है जो भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इसके साथ-साथ प्रत्येक भारतीय को कागज विहीन तरीके से वित्त की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

भारत का पहला लोकपाल

लंबे प्रयासों और तमाम आंदोलनों के बाद आखिरकार भारत को पहला लोकपाल मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष 19 मार्च 2019 को देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत में लोकपाल लाने में 59 साल लग गए, जबकि दुनिया में लोकपाल कानून का इतिहास लगभग 210 साल पुराना है।

क्या है

1. देश के पहले लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने की थी।
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड्गे भी समिति के सदस्य हैं, लेकिन वह लोकपाल की पिछली कई बैठकों से शामिल नहीं हो रहे थे। जस्टिस पीसी घोष के चयन में भी वह शामिल नहीं रहे हैं।
3. जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (पीसी घोष), जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। उन्होंने कोलकाता से कानून की पढ़ाई पूरी की और साल 1997 में वह कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बन गए। दिसंबर 2012 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उन्होंने एआइएडीएमके (AIADMK) की पूर्व सचिव शशिकला को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाई थी।

4. इसके बाद 8 मार्च 2013 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और 27 मई 2017 को वह सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी जुड़े रहे थे।

भारत में लोकपाल का सफर

1. भारत में लोकपाल का सफर अब से करीब 59 साल पहले 1960 में शुरू हुआ, जब केएम मुंशी ने संसद में लोकपाल मुद्दे को उठाया था।
2. इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 की सिफारिश पर करीब 51 साल पहले 9 मई 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश हुआ था। उस वक्त लोकपाल विधेयक में प्रधानमंत्री को भी रखा गया था।
3. 1971 में पीएम पद को लोकपाल के दायरे से हटा लिया गया। 1977 और 1985 में प्रधानमंत्री पद को फिर से लोकपाल के दायरे में लाया गया। 1989 में वीपी सिंह सरकार ने इसमें वर्तमान और निवर्तमान प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया। 1996 में एचडी देव गौड़ा और फिर 1998 व 2001 में भाजपा सरकार ने भी इस विधेयक में प्रधानमंत्री पद को शामिल किया था। हालांकि, उस वक्त तक नौकरशाह इस विधेयक में शामिल नहीं थे।
4. वर्ष 2002 में वेंकट चेलैया आयोग ने संविधान समीक्षा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की सख्त आवश्यकता बताई थी। इसके बाद 2005 में वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने भी लोकपाल की जरूरत सरकार के सामने रखी।
5. 2011 में भी प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने लोकपाल की जरूरत पर बल दिया। इस तरह 8 नाकाम प्रयासों के बाद भारत का लोकपाल बिल 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा और अगले दिन (18 दिसंबर 2013) को लोकसभा में पास हो गया। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी तत्काल बिल को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद भी भारत को पहला लोकपाल मिलने में सवा पांच साल का वक्त लग गया।
6. दुनिया में सबसे पहला लोकपाल वर्ष 1809 में स्वीडन देश में तैनात किया गया था। स्वीडन समेत दुनिया के अन्य देशों में लोकपाल को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है। इसे नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है।
7. यह एक ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च पद है जो लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करता है। साथ ही संबंधित जांच-पड़ताल कर उसके खिलाफ उचित कार्यवाही उचित कार्यवाही कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश भी करता है। ऑम्बुड्समैन को भी भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाता है। यह नामकरण 1963 में भारत के मशहूर कानूनविद डॉ एलएम सिंघवी ने किया था। लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त राज्य में होता है। लोकपाल शब्द संस्कृत के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।
8. स्वीडन के बाद धीरे-धीरे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डिनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व यूरोप के की देशों में भी ऑम्बुड्समैन की नियुक्तियां की गईं।
9. फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क ने 1954 में, नार्वे ने 1961 में और ब्रिटेन ने 1967 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ऑम्बुड्समैन की स्थापना की थी।
10. भारत से पहले, 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है। विभिन्न देशों में ऑम्बुड्समैन को भिन्न भिन्न को भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है।
11. ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से पहचानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक््यूटर के नाम से जाना जाता है।

न्यायमूर्ति पी.सी. घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नामित किया गया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है। 67 वर्षीय जस्टिस घोष जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति द्वारा उनके नाम को अंतिम रूप दिया गया और सिफारिश की गई।

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 (ए)

राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत आयोग के साथ पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक दल को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा कराना होता है।

क्या है

1. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्था को पार्टी के प्रस्तावित नाम को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को कहा जाता है।
2. इस प्रकार के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तावित पंजीकरण के बारे में यदि कोई आपत्ति हो तो उन्हीं समाचार पत्रों में दो दिन तक उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होता है।
3. आयोग ने लोकसभा और आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए 10 मार्च, 2019 को चुनाव कराने की घोषणा की है। इसलिए, वर्तमान चुनावों को देखते हुए, आयोग ने एक बार समय में छूट दी है और 10 मार्च, 2019 अर्थात् चुनाव की घोषणा वाली तिथि को अपने सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराने वाले दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है।

रासायनिक हमले से हिफाजत करेगा एनबीसी सूट-बूट

न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल (एनबीसी) सूट अब छह घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे तक रासायनिक हमले से सैनिकों की हिफाजत करेगा। रासायनिक हथियारों से निकलने वाली तबून, सरीन, सल्फर मस्टर्ड व क्लोराइडजैसी विषाक्त गैसों को बेअसर करने के लिए डीआरडीओ ने एनबीसी वॉरकेयर प्रोटेक्शन सूट, बूट और ग्लव्स तैयार किए हैं। प्राथमिक ट्रायल सफल होने के बाद अब इसका परीक्षण अंतिम चरणों में चल रहा है।

क्या है

1. 24 मार्च 2019 को राजकीय चर्म संस्थान के पूर्व छात्र सम्मेलन में शामिल में शामिल शिरकत करने आए डीआरडीओ में टेक्निकल ऑफीसर मनोज सिंह ने बताया कि एनबीसी सूट का नया वर्जन मार्क-6 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल व केमिकल वारफेयर प्रोटेक्शन सूट 'एक्टिवेट कार्बन' 'फाइबर पोलिस्टर' फ्रैब्रिक सूट शक्तिवेट कार्बनश श्फाइबरश, श्पोलिस्टरश व श्फैब्रिकश से बना है। यह ज्यादा प्रभावी है और परीक्षण में बेहतर परिणाम मिले हैं।
2. कंप्रेशर मोल्डिंग तकनीक से तैयार मार्क-2 बूट ब्रोमोबुटाइल रबर से बनाए गए हैं। यह पहले से अधिक क्षमतावान है। रसायन व गैसों से बचाव करने के साथ यह बूट हल्की एल्फा व बीटा किरणों को भी रोकता है। ब्रोमोबुटाइल रबर के अलावा यह बूट कार्बन कंटेंट, सिल्वर पार्टिकल व नैनो पार्टिकल से बनाया गया है। जिसका वजन महज नौ सौ ग्राम है।
3. यह बूट डीएमएस शूज के ऊपर पहना जाता है। यह फ्लेक्सिबल भी है। बूट के अलावा मार्क-2 एनबीसी दस्ताने भी बनाए गए हैं जिसमें कॉटन फ़ैब्रिक व ब्रोमोबुटाइल रबर की दो लेयर का इस्तेमाल किया गया है।
4. बेहद ठंडे सरहदी इलाकों में व्हाइट नापा लेदर से बने दस्ताने सैनिकों के हाथों को -40 डिग्री न्यूनतम तापमान पर भी सुरक्षित रख रहे हैं।
5. टेक्सटाइल, पीयू कोटेड फ़ैब्रिक, नायलॉन व पायल फ़ैब्रिक से यह दस्ताने बनाए गए हैं। वहीं रबर फ़ैब्रिक व कॉटन ड्रिल से ऐसे जूते भी बनाए गए हैं जो सैनिकों के पैरों को गलन से बचाएंगे।
6. इन जूतों को शू एंड शू कहा जाता है जिसकी प्रतिवर्ष 125 लाख जोड़ियों लाख जोड़ियों की जरूरत होती है और इसकी जरूरत को पूरा भी किया जा रहा है।

भूगर्भ जल का दोहन पर वाटरएड की रिपोर्ट

भूगर्भ जल दोहन पर गैर सरकारी संस्था वाटरएड की हालिया रिपोर्ट आपके माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर सकती है। इसमें बताया गया है कि विश्व भर में भूगर्भ जल का जितना दोहन होता है, उसका करीब एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत निकालता है। इतना जलदोहन अमेरिका और चीन मिलकर भी नहीं करते। भारत में वर्ष 2000-10 के बीच भूगर्भ जल के नीचे गिरने का स्तर 23 फीसद हो गया है। जल दिवस (22 मार्च) के मद्देनजर जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर भूगर्भ जल का 24 फीसद अकेले भारत उपयोग करता है।

क्या है

1. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अनाज और कपड़ों का निर्यात भारत की आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया है। यदि इनके उत्पादन व्यवस्था को टिकाऊ नहीं बनाया गया तो समस्या बढ़ भी सकती है। गरीब वर्ग के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
2. वाटरएड ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया है 'बिनीथ 2019' है-बिनीथ द सरफेस: द स्टेट आफ द वर्ल्ड्स वाटर 2019। इसमें कहा गया है कि विश्व में भारत भूगर्भ जल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वह 12 फीसद भूगर्भ जल का निर्यात करता है।
3. भारत में धान और गेहूँ के उत्पादन में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। एक किलो गेहूँ के लिए औसतन 1,654 लीटर और एक किलो चावल उपजाने के लिए औसतन 2,800 लीटर पानी की जरूरत होती है।
4. रिपोर्ट में सुझाया गया है कि अगर धान और गेहूँ की जगह भारत में मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज का उत्पादन किया जाए तो इससे सिंचाई जल की जरूरत एक तिहाई कम हो जाएगी।
5. वाटरएड इंडिया के मुख्य कार्यकारी वीके माधवन ने कहा कि विश्व जल दिवस अधिक पानी की खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने और उपभोक्ताओं को उनकी खरीद को अधिक विचारशील बनाने का आह्वान करता है। स्वच्छ जल की कमी कमजोर तबके को गरीबी की तरफ धकेलती है।

जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम को पांच साल आगे बढ़ा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम (बीआरसीपी) और वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी)/डीबीटी इंडिया एलायंस को इसकी आरम्भिक 10 वर्षीय अवधि (2008-09 से 2018-19 तक) से आगे बढ़ाकर नये पंचवर्षीय चरण (2019-20 से 2023-24 तक) में भी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। उधर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपनी प्रतिबद्धता डब्ल्यूटी की तुलना में दोगुनी बढ़ा दी है। इस निर्णय से कुल वित्तीय बोझ 1092 करोड़ रुपये का पड़ेगा जिसमें डीबीटी और डब्ल्यूटी क्रमशः 728 करोड़ एवं 364 करोड़ रुपये का योगदान करेंगे।

क्या है

1. इस कार्यक्रम ने 1:1 साझेदारी में अपने 10 वर्षीय वित्त पोषण के दौरान भारत में अत्याधुनिक जैव चिकित्सा (बायोमेडिकल) अनुसंधान में उच्चतम वैश्विक मानकों वाली प्रतिभाओं के सृजन एवं शिक्षण से संबंधित अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां और अनुप्रयोग संभव हो पाए हैं।
2. बीआरसीपी से विदेश में काम कर रहे बेहतरीन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वदेश वापस आना आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही बीआरसीपी की बदौलत भारत में कई स्थानों पर ऐसे केंद्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जहां विश्वस्तरीय जैव चिकित्सा अनुसंधान किए जाते हैं।
3. इस कार्यक्रम के विस्तार वाले चरण के दौरान इस क्षमता को बढ़ाने का क्रम जारी रखा जाएगा और इसके साथ ही भारत में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए नैदानिक अनुसंधान और कार्य को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
4. भारत सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी अपेक्षित परिणाम हासिल हो पाएंगे।

भारत में अगली जनगणना

भारत में अगली जनगणना 2021 में की जाएगी। उस साल की एक मार्च की तारीख उसकी आधार तिथि होगी। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह घोषणा की। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या 37) की धारा तीन के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला किया।

क्या है

1. इसमें कहा गया कि भारत की जनसंख्या की गणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी।
2. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिमपात प्रभावित इलाकों को छोड़कर जनगणना की आधार तारीख एक मार्च 2021 रात 12 बजे होगी।
3. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों के लिए आधार तारीख एक अक्टूबर 2020 होगी।
4. भारत की पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और तब देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी।

मित्र शक्ति-VI की शुरूआत

भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के 14 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति-VI की दियातलावा, बदूला, श्रीलंका में दियातलावा परेड ग्राउंड में 27 मार्च को शुरूआत हुई। दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास का यह छठा संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 26 मार्च से शुरू होकर 08 अप्रैल, 2019 तक चलेगा।

क्या है

1. भारतीय सेना की टुकड़ी में बिहार रेजीमेंट का कंपनी समूह और इतनी ही क्षमता में श्रीलंका की सेना की जेमूनू वॉच बटालियन शामिल थी।
2. श्रीलंका की सेना की 21वीं डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर एचपीएनके जयपतिराणा उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।
3. युद्धाभ्यास में मुख्य रूप से विद्रोही गतिविधियों और संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत शहरी / ग्रामीण माहौल में आतंकवादी कार्रवाईयों से निपटने के लिए टुकड़ियों को प्रशिक्षित करना और सुसज्जित करना है। युद्धाभ्यास दोनों टुकड़ियों दोनों टुकड़ियों को एक आदर्श मंच प्रदान करता है ताकि वे अपने परिचालन अनुभव और विशेषज्ञता को साझा कर सकें।
4. साथ ही यह युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच पारस्परिकता और सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

अन्तरराष्ट्रीय

ओबीओआर के साथ जुड़ने वाला G-7 का पहला देश

चीन के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के साथ अब यूरोपीय देश इटली भी जुड़ गया है। इटली ने चीन के साथ एक मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव (ओबीओआर) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त पहल के तहत दोनों देश अफ्रीका, यूरोप और अन्य महाद्वीपों में बंदरगाह, पुल और बिजलीघर का निर्माण कार्य करेंगे। इटली जी-7 का पहला देश है जिसने चीन के साथ इतनी महत्वपूर्ण भागीदारी शुरू की है। यूरोपी में चीन के दखल के तौर पर विश्लेषक इसे देख रहे हैं।

क्या है

1. जी-7 का पहला देश है इटली जिसने चीन के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट में भागीदार बनने पर सहमति जताई। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के हालात बने हैं, चीन की कोशिश यूरोपीय देशों को अपने साथ करने की है।
2. इटली और चीन की इस निकटता से वॉशिंगटन को खासी नाराजगी है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के भी कई देश इसे यूरोप में चीन के दखल बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।

3. यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने चीन के संवेदनशील तकनीक हासिल करने और महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब में कब्जा करने को लेकर आशंका भी जताई है।
4. **जी-7 देशों में अमेरिका भी शामिल है** और जाहिर है कि इटली के इस कदम के बाद स्वाभाविक तनातनी बढ़ सकती है। इटली को उम्मीद है कि इस कदम के जरिए वह अपने देश के पारंपरिक बंदरगाहों को नए सिरे से प्रभावी कर सकता है जो पूर्व और पश्चिम के बीच लिंक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। **इटली और चीन के बीच 2.5 बिलियन यूरो का समझौता हुआ है।**

अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019

भारत और अफ्रीकी देशों के लिए **अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019** (एफआईएनडीईएक्स-19) का उद्घाटन समारोह 18 मार्च, 2019 को औंध मिलिट्री स्टेशन, पुणे में आयोजित हुआ। यह अभ्यास कार्यक्रम 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक चलेगा। 17 अफ्रीकी देशों - बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिंबाब्वे के सैन्य दल के साथ मराठा लाइट इन्फैंट्री ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

क्या है

1. **मराठा लाइट इन्फैंट्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।** मेजर जनरल संजीव शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, गोल्डन कटार डिवीजन, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागी देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ परेड की समीक्षा की।
2. उद्घाटन समारोह में **चीता हेलिकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों** ने संयुक्त राष्ट्र, भारत और **एफआईएनडीईएक्स-19** के झंडे लहराए। परेड की समाप्ति पर मुख्य अतिथि और अफ्रीकी देशों के रक्षा अधिकारियों ने परेड के प्रतियोगियों के साथ बातचीत की।
3. **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि के अध्याय VII** के तहत मानवीय सहायता और शांति स्थापना गतिविधियों के लिए योजना बनाना और इसका परिचालन इस अभ्यास के उद्देश्य है।
4. यह अभ्यास प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई कार्य योजना में शामिल हैं ख नये मिशन की स्थापना, शांति स्थापना गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए स्थल चयन, सैन्य पर्यवेक्षक के लिए स्थल चयन, नागरिकों की सुरक्षा, युद्धक तैनाती, सैन्य दल की सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए निगरानी के विभिन्न आयाम।

भारत-अमेरिका के बीच हुआ अहम समझौता

भारत-अमेरिका के बीच 27 मार्च 2019 को एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। **ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी एग्रीमेंट (Inter and Governmental Agreement)** है। इसके बाद दोनों देशों के बीच **कंटी-बाइ-कंटी (CbC) रिपोर्टों का आदान-प्रदान सुगम हो सकेगा।** इसका सीधा लाभ दोनों देशों में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलेगा। इस समझौते के साथ **द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण** की व्यवस्था भी भारत-अमेरिका के बीच लागू हो जाएगी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ऑटोमैटिक तरीके से सीबीसी रिपोर्ट का आदान-प्रदान आसान हो जाएगा। ये सीबीसी रिपोर्ट संबंधित कर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मूल संस्थाओं द्वारा दायर की जाती हैं। ये समझौता एक जनवरी 2016 को या उसके बाद संबंधित न्यायालयों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अंतिम मूल संस्थाओं द्वारा दायर सीबीसी रिपोर्टों पर लागू होगा।

क्या होती है सीबीसी रिपोर्ट

1. **ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन और कंटी-बाइ-कंटी रिपोर्टिंग**, बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) को सालाना रिपोर्ट करने के लिए और प्रत्येक कर क्षेत्र के लिए एक खाका प्रदान करती है।
2. इसमें वे व्यापार की जानकारी साझा करते हैं। इसी रिपोर्ट को **Country and by & and & Country (CbC)** रिपोर्ट कहा जाता है।

3. ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सहयोग भी तेजी से बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच अधिकारियों की यात्राएं बढ़ी हैं।
4. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता राबर्ट पलाडिनो ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हमारी मजबूत सामरिक भागीदारी से दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे (अमेरिका के) प्रमुख सुरक्षा भागीदारों में से एक है।

अंटार्कटिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंटार्कटिक सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के साथ साथ अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मुख्य विशेषताएं

1. अन्य बातों के अलावा पृथ्वी विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्रों के साथ ही अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागरों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनके संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में वैज्ञानिक सहयोग;
2. अंटार्कटिका, उसके पर्यावरण और उसके आश्रित और उससे जुड़ी पर्यावरण प्रणालियों के अध्ययन से जुड़ी वैज्ञानिक और ग्रंथात्मक जानकारी का आदान प्रदान आदान ख प्रदान;
3. वैज्ञानिकों के आदान प्रदान के लिए अवसरों का पता लगाना;
4. आवश्यकता पड़ने पर एक देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों का अन्य देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में भाग लेना;
5. संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं; जहां कहीं संभव हो, वहां प्रमुख धुनीय मंच की बैठकों के दौरान द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करें;
6. संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशन;
7. वैज्ञानिक कर्मियों का प्रशिक्षण;

जल प्रबंधन कार्यशाला के साथ विश्व जल दिवस को मनाया गया

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 22 मार्च, 2019 को विश्व जल दिवस के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के सहयोग और यूनिसेफ इंडिया के समर्थन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल प्रबंधन (ग्रे वाटर) और आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जल शोधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला (21 और 22 मार्च) का आयोजन किया। कार्यशाला के पूर्ण सत्र को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेस्वरन अय्यर, और आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति ने संबोधित किया।

क्या है

1. आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित जल पर एक रिपोर्ट सिंहावलोकन और नीतिगत पहलू प्रस्तुत किए गए, जिसमें जल स्तरों के दूषित प्रभावों के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण संदूषण, स्वास्थ्य प्रभावों और संचार रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
2. धूसर जल नीति पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों और भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान कृषि और भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल पुनः उपयोग के लिए मानक तय करने पर भी जोर दिया गया।
3. कार्यशाला के दौरान सरल सोख गड्डों से लेकर फाइटो-रिमेडिशन और झिल्ली आधारित धूसर जल शोधन जैसी विभिन्न जैसी विभिन्न तकनीकों पर चर्चा के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली तकनीकों को सरल बनाने की जरूरत है, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए कौशल स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता है।

4. राज्यों के सत्र में, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब की राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल प्रबंधन पर अपने-अपने अनुभव प्रस्तुत किये। इसके अलावा धूसर जल शोधन इकाइयों के निर्माण के लिए विभिन्न विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच और लाभकारी स्वास्थ्य एवं इनके आर्थिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया।
5. प्रौद्योगिकी सत्र के दौरान स्थानीय स्तर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण संदूषण को दूर करने के लिए विभिन्न विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
6. इनमें नैनो तकनीक आधारित समाधान, **झिल्ली प्रौद्योगिकी और फ्लोराइड शोधन के लिए समुदाय** आधारित दृष्टिकोण शामिल थे। आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने प्रदूषण संदूषण से मुक्त पेय जल उपलब्ध कराने की रणनीतियां भी प्रस्तुत की।

भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 286 की उप-धारा 4 में अपेक्षित है कि भारत में निवासी किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्था या मूल संस्था के अलावा किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की संघटक संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के लिए उस अन्तर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में देश-दर-देश(सीबीसी) रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, बशर्ते कि कथित अन्तर्राष्ट्रीय समूह की मूल संस्था किसी ऐसे देश या क्षेत्र की निवासी हो-

1. जहां मूल संस्था को सीबीसी रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता नहीं है,
2. जिस देश के साथ भारत का सीबीसी रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है, या
3. जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और ऐसी विफलता को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी संघटक संस्था को सूचित किया गया हो।

क्या है

1. 18 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी अधिसूचना जीएसआर 1217(ई) दिनांक 18 दिसम्बर द्वारा आयकर नियमावली 1962 ('नियमावली') में संशोधन किए गए हैं ताकि सीबीसी रिपोर्ट (स्थानीय रूप से दाखिल) जमा करने के लिए रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद से 12 महीने की अवधि उपलब्ध कराई जा सके।
2. इसके अलावा अधिनियम की धारा-119 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिपत्र संख्या 9/2018, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के द्वारा एक बार के उपाय के रूप में रिपोर्टिंग लेखा वर्षों के संबंध में सीबीसी रिपोर्ट (स्थानीय रूप से) 28 फरवरी, 2018 या उससे पूर्व दाखिल करने की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
3. भारत और अमरीका के बीच अब तक ऐसा समझौता न होने से अब भारत में सीबीसी रिपोर्ट को स्थानीय रूप से जमा करने की संभावना बढ़ गई है। तथापि एक आधारभूत अंतर-सरकारी समझौते के साथ भारत और अमरीका में सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए 'द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण प्रबंधन' को अब अंतिम रूप दिया गया है और इस पर 31 मार्च 2019 को या इससे पहले हस्ताक्षर किये जायेंगे।
4. इससे दोनों देश एक जनवरी, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंधित अधिकार क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय समूहों की अंतिम मूल संस्थाओं द्वारा दाखिल सीबीसी रिपोर्ट का आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे।
5. जिसके परिणामस्वरूप अमरीका में मुख्यालय वाले अन्तर्राष्ट्रीय समूहों की वे भारतीय संघटक संस्थाएं, जिन्होंने अपनी सीबीसी रिपोर्ट पहले ही अमरीका में दाखिल कर दी हैं, उन्हें भारत में अपने अन्तर्राष्ट्रीय समूहों की सीबीसी रिपोर्ट स्थानीय रूप से दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

बोलिविया के साथ आठ समझौता

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 मार्च, 2019 की शाम को बोलिविया के शांताक्रूज स्थित वीरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां उनका स्वागत बोलिविया के राष्ट्रपति श्री इवो मोरेल्स आईमा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। इस अवसर पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और बोलिविया के

बीच यह अब तक का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। राष्ट्रपति ने 29 मार्च, 2019 को बोलिविया के राष्ट्रपति श्री इवो मोरेल्स आईमा के साथ बैठक के द्वारा अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। राष्ट्रपति मोरेल्स के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि बोलिविया में भारत की अब तक की पहली राजकीय यात्रा करके वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विशेष स्वागत एवं प्रेम के लिए राष्ट्रपति मोरेल्स को धन्यवाद दिया।

क्या है

1. इसके बाद राष्ट्रपति के नेतृत्व में दोनों पक्षों के बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देखना बहुत उत्साहवर्धक है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारत-बोलिविया द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और 2018 के दौरान यह 875 मिलियन डॉलर का रहा।
2. बोलिविया के सोने का 60 प्रतिशत भारत को निर्यात होता है। बोलिविया लातिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का आठवां अग्रणी व्यापार साझेदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपने व्यापार बास्केट को विविधीकृत बनाने की आवश्यकता है।
3. राष्ट्रपति ने कहा कि हम फार्मा क्षेत्र में अपने निर्यात को बढ़ाने के इच्छुक हैं। भारत को सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय फार्मा कंपनियाँ बोलिविया को सभी के लिए स्वास्थ्य के अपने महान विज्ञान में मदद कर सकती हैं।
4. दोनों पक्षों ने बोलिविया के विशाल लिथियम भंडार की खोज और निष्कर्षण के लिए एक साथ काम करने के लिए भी सहमति जताई। लिथियम बैटरी बनाने में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भारत को इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते उपयोग जैसी अपनी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलों के लिए चाहिए।
5. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विकासशील देशों के सहयोग के ढांचे के तहत बोलिविया के साथ अपनी विकास सहयोग साझेदारी पर गर्व करता है। उन्होंने बोलिविया द्वारा चुने जाने वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बोलिविया को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की ऋण सहायता की। उन्होंने बोलिविया में भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट को दोगुना करके दस तक लाने की पेशकश की।
6. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद, दो राष्ट्रपतियों ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और उनका आदान-प्रदान किया, जिनमें संस्कृति के क्षेत्र, राजनयिकों के लिए वीजा छूट, राजनयिक अकादमियों के बीच आदान-प्रदान, खनन, अंतरिक्ष, पारंपरिक चिकित्सा, आईटी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और द्विसामुद्रिक रेलवे परियोजना शामिल है।
7. भारत ने इस परियोजना पर बोलिविया के साथ काम करने के लिए भारतीय रेलवे की संभावना तलाशने की पेशकश की जो बोलिविया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, बोलिविया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर संरचना समझौते पर हस्ताक्षर करने के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हुआ।
8. इसके बाद, राष्ट्रपति मोरेल्स ने राष्ट्रपति कोविंद को बोलिविया के सबसे बड़े राज्य सरकारी सम्मान - कोडोर डी लॉस एंडीज एन एल गादो डी ग्रान कॉलर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार भारत और बोलिविया के बीच की दोस्ती को समर्पित किया। इस अवसर पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

मोजाम्बिक में भयंकर समुद्री तूफान

दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में आए भयंकर समुद्री तूफान से बड़ी तबाही मची है। एक हजार से ज्यादा लोगों के तूफान में मारे जाने की आशंका है। तूफान ने पड़ोसी जिम्बाब्वे में भी खूब तबाही मचाई है। वहां दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। समुद्री तूफान इडाई को मोजाम्बिक के बेरा शहर में अपने साथ तबाही लेकर आया। तेज हवा और अचानक बाढ़ से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी अपने साथ हजारों घरों और सड़कों को बहा ले गया है।

क्या है

1. राष्ट्र के नाम अपने संदेश में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी ने कहा 'अभी कहा, शअभी तक आधिकारिक रूप से 84 मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन सही लेकिन असल आंकड़ा तब सामने आएगा जब हवाई सर्वे किया जाएगा। वैसे अनुमान

है कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है' हुई है। उन्होंने इसे भयानक आपदा बताया है। उन्होंने बताया कि एक लाख से ज्यादा लोग खतरे में हैं।

2. **मिशन एविग्रेशन फेलोशिप नाम** की एक गैर लाभकारी संस्था की ओर से जारी हवाई फोटोग्राफ में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ का पानी घरों की खिड़कियों तक पहुंच गया है।
3. इससे हजारों लोग अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं। वहीं, रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 5 लाख आबादी वाले शहर करीब 90 फीसदी तबाह या क्षतिग्रस्त हो गया है।
4. रेडक्रॉस सोसायटी के मुताबिक, स्थिति बहुत भयावह है। बड़े पैमाने पर तबाही मची है।

अमेरिकी प्रतिबंधों का कसता पेंच

अमेरिका के प्रतिबंधों की पकड़ जहां मजबूत होती जा रही है वहीं ईरान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी चुनौतियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब वह अपने सुदूर दक्षिण-पूर्व में मौजूद महज एक बंदरगाह के जरिये सामानों के प्रवाह को जारी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर चाबहार में मौजूद बंदरगाह गल्फ के बाहर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जिसे 2018 में अमेरिका द्वारा दोबारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है।

क्या है

1. चाबहार के लोकेशन के भी अपने खतरे हैं क्योंकि यह रेगिस्तान यह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है जहां आतंकी संगठन मौजूद हैं।
2. पिछले साल दिसंबर में एक सूइसाइड अटैक में स्थानीय पुलिस हेडक्वार्टर के दो कर्मी मारे गए थे। फरवरी में इसलिए निवेश सम्मेलन के दौरान सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। सुरक्षा के अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पेमेंट लेने और देने में ईरान को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
3. इस अनिश्चितता के बीच मालदुलाई से संबंधित कंपनी चलाने वाली राबियानी चाबहार को उन लोगों के लिए अवसर मानती हैं जो खतरा मोल लेना चाहते हैं।
4. मैं पिछले डेढ़ साल से चाबहार पर शोध कर रही हूँ, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और अब यहां गंभीर काम किया जा सकता है।
5. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से हम प्रतिबंधों में हैं और हम उसका सामना करने के लिए काम कर रहे हैं।' रहे हैं।

वेनेजुएला संकट

वेनेजुएला की नेशनल की नेशनल असेंबली के स्पीकर जुआन गुएदो ने कहा है कि वह संविधान के उस अनुच्छेद को लागू करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें देश में अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को बुलाने की अनुमति देता है जिससे वे उन्हें सहयोग प्रदान कर सकें। गुएदो को 50 देशों द्वारा वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया है।

क्या है

1. गुएदो ने मिरांडा प्रांत में समर्थकों के एक समूह से कहा, जब हमने अनुच्छेद 187 के बारे में बात की और हमने कहा था कि निश्चित रूप से हम इसे लागू करने जा रहे हैं।
2. उन्होंने कहा, 'हम कहा, शहम उस सहयोग पर जोर देने जा हैं' रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के कुछ लोगों कुछ धड़ों ने संविधान के अनुच्छेद 187 धारा 11 अनुच्छेद 187.11 लागू करने के लिए कहा है जो इस देश में वेनेजुएला के सैन्य अभियानों या विदेशी मिशनों को काम करने की अनुमति देता है।
3. वेनेजुएला में विपक्ष का कहना है कि देश एक जटिल मानवीय संकट में डूबा हुआ है और उसने आपातकाल को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दान व सहायता मांगी है।

#MeToo की तरह #KuToo अभियान

जापान में पश्चिमी देशों में शुरू हुए #MeToo अभियान की तरह एक अभियान #KuToo चल रहा है। जापान के दफ्तरों में महिलाओं को हाई हील्स पहनना अनिवार्य है। हाई हील के कारण कई बार महिलाओं को कई तरह की शारीरिक परेशानी भी होती है। जापान टाइम्स के अनुसार, इसी के विरोध में महिलाओं ने सोशल मीडिया पर यह अभियान शुरू किया है। दफ्तरों में अनिवार्य ड्रेसकोड और महिलाओं के लिए हाई हील्स अनिवार्य रहने के विरोध में यह अभियान चलाया जा रहा है। क्या है

1. जापान में ड्रेसकोड और हाई हील्स के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है।
2. सोशल मीडिया यूजर्स हाई हील्स और फॉर्मल ड्रेस कोड अनिवार्य रखने को पुरानी सामंती मानसिकता को ही आगे ले जानेवाली परंपरा बताई जा रही है।
3. हाई हील्स के विरोध में महिलाओं का तर्क है कि इससे एड़ी में दर्द, कमर दर्द जैसी कई शारीरिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है।
4. महिलाओं ने इसके विरोध में लिखा, 'जूते लिखा, शजूते पहनने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यह एक तरह की औरतविरोधी मानसिकता है, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य की अनदेखी कर हाई हील्स पहनने पड़ते हैं।' पड़ते हैं।
5. जापान के दफ्तरों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही ड्रेसकोड अनिवार्य है। पुरुषों को भी फॉर्मल ड्रेसकोड के साथ क्लीनशेव रहना अनिवार्य है। महिलाओं के ड्रेसकोड में हाई हील्स भी अनिवार्य है।

आतंक के खिलाफ एससीओ के प्रमुख

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों का द्विपक्षीय ढंग से समाधान होना चाहिए। आतंकवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ 'बिना शर्त' लड़ाई की प्रतिबद्धता के बगैर दोनों देशों का एससीओ में शामिल होना असंभव है। नोरोव ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में प्रतिबद्धता की बात कर सीधे तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा है।

क्या है

1. हाल ही में एससीओ प्रमुख बने नोरोव ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि पुलवामा आतंकी हमला भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के विरोधियों की ओर से किया गया सीधे तौर पर उकसाने वाला कृत्य था।
2. उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया हालात के कारण लोग हताहत हुए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के विरोधियों की ओर से किया गया उकसाने वाला कृत्य था।'
3. यह पूछे जाने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए एससीओ की व्यवस्था का कैसे इस्तेमाल हो सकता है तो नोरोव ने कहा कि एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने से पहले दोनों देशों को आतंकवाद एवं अलगाववाद के

फ़्लैशबैक

1. शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का राजनीतिक आर्थिक, और सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की।
2. 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया।
3. चीन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और तजाकिस्तान ने 1996 में 'शंघाई V' नाम से संगठन की स्थापना शंघाई में की।
4. सन् 2001 में वापस शिंघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर 'शंघाई VI' में बदल दिया गया जो अब शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) या SCO नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

खिलाफ 'बिना शर्त' लड़ाई की प्रतिबद्धता पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा किए बिना दोनों देशों का एससीओ में शामिल होना असंभव है।

अर्थशास्त्र

जीएसटी काउंसिल बैठक में नई दरों को मंजूरी

जीएसटी काउंसिल ने 19 मार्च 2019 की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए की गई दरों में कटौती की व्यवस्था को लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राजस्व सचिव ए बी पांडेय ने कहा कि राज्यों से बातचीत कर डिवेलपर्स को नई व्यवस्था के तहत आने के लिए जरूरी समय मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स निर्माणाधीन रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए दो टैक्स स्लैब में किसी का चयन कर सकते हैं।

क्या है

1. काउंसिल की बैठक में बिल्डर्स को दो विकल्प दिए जाने का फैसला हुआ है। उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 फीसद का भुगतान करना होगा या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना उन्हें 5 फीसद टैक्स का भुगतान करना होगा।
2. वहीं किफायती हाउसिंग के मामले में उन्हें टैक्स छूट के साथ 8 फीसद का भुगतान करना होगा या फिर बिना छूट के 1 फीसद टैक्स का भुगतान करना होगा।
3. बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दरों में की गई कटौती की नई व्यवस्था को लागू करने और उससे जुड़े अन्य मसलों पर चर्चा की गई।
4. गौरतलब है कि 24 फरवरी को हुई पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए जीएसटी दर को घटाकर पांच फीसद और किफायती श्रेणी के मकानों के लिए इस दर को घटाकर एक फीसद कर दिया गया था। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
5. अभी निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए होने वाले भुगतान पर जीएसटी की दर 12 फीसद है और इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का प्रावधान भी है।
6. यही व्यवस्था ऐसे रेडी-टु-मूव-इन फ्लैट्स के लिए भी है, जिनके लिए बिक्री के वक्त कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए गए होते हैं। किफायती श्रेणी में आने वाली आवासीय इकाई के लिए अभी जीएसटी की दर आठ फीसद है।
7. जीएसटी वसूली फरवरी महीने में घटकर 97,247 करोड़ रुपये पर आ गई है, जो जनवरी में 1.02 लाख करोड़ रुपये रही थी।
8. फरवरी में हुई वसूली में सेंट्रल जीएसटी 17,626 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 24,192 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी 46,953 करोड़ रुपये और सेस 8,476 करोड़ रुपये का रहा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी वसूली का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

आईबीबीआई और सेबी मे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने 19 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। आईबीबीआई और सेबी दरअसल दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 और इससे संबंधित नियम-कायदों पर कारगर ढंग से अमल किए जाने के पक्ष में हैं, जिन्होंने डेट एवं इक्विटी के आपसी रिश्तों आपसी ताल्लुकात को नए सिरे से परिभाषित किया है और जिनका उद्देश्य उद्यमिता एवं डेट मार्केट को बढ़ावा देना है। आईबीबीआई और सेबी ने सहमति पत्र के तहत संहिता के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। उपर्युक्त एमओयू पर सेबी के कार्यकारी निदेशक श्री आनंद बैवर और आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री रितेश कावड़िया ने मुंबई में हस्ताक्षर किए।

उपर्युक्त एमओयू में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:

1. दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं को साझा को साझा किया जा सकेगा। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा।
2. एक-दूसरे के साथ उपलब्ध संसाधनों को उस हद तक साझा तक साझा किया जा सकेगा जिस हद तक यह व्यवहार्य और कानूनन उचित होगा।
3. आपसी हितों वाले विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें की जाएंगी। एक-दूसरे की जवाबदेही पर असर डालने वाली नियामकीय आवश्यकताएं, प्रवर्तन से जुड़े मामले, अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा को साझा करना इन विषयों में शामिल हैं। इसके अलावा, कोई भी ऐसा अन्य मुद्दा इनमें शामिल है जिनके बारे में संबंधित पक्षों को यह प्रतीत होता है कि उनकी संबंधित वैधानिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में वह एक-दूसरे के हित में होगा।
4. एक-दूसरे के कर्मचारियों या स्टाफ को प्रशिक्षण देना, ताकि प्रत्येक पक्ष को सामूहिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए दूसरे पक्ष के मिशन की बेहतर समझ हो सके।
5. दिवाला से जुड़े प्रोफेशनलों और वित्तीय ऋणदाताओं का क्षमता निर्माण करना।
6. संहिता के विभिन्न प्रावधानों, इत्यादि के तहत मुश्किलों से जूझ रहे विभिन्न तरह के कर्जदारों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अहमियत एवं आवश्यकता के बारे में वित्तीय ऋणदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना।

एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए दी सशर्त मंजूरी

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कर्ज से लदी एस्सार स्टील के लिए पेश की गई वैश्विक दिग्गज स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के समाधान योजना को सशर्त मंजूरी दे दी है। आर्सेलर मित्तल ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। एनसीएलएटी ने कहा है कि उसकी यह मंजूरी पूर्व के आदेश पर एस्सार स्टील के प्रमोटर्स की तरफ से दायर की गई अपील पर आने वाले निर्णय से तय होगी। जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि एस्सार स्टील की समाधान योजना पर कोई रोक नहीं है और मिलने वाले फंड को कंपनी को कर्ज देने वालों के बीच बांटा जाएगा।

क्या है

1. ट्रिब्यूनल ने कहा, 'समाधान कहा, समाधान योजना को तैयार करने वाल पेशेवर निगरानी कमेटी के चेयरमैन होंगे और वह कानून के मुताबिक काम करेगा'। काम करेंगे।
2. अपील ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच होने वाले फंड के वितरण के मामले को भी देखेगा।
3. पीठ ने इंसांत्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) से दोनों तरह के कर्जदाताओं के बीच होने वाले फंड वितरण का अनुपात तय करने को कहा है।
4. एस्सार स्टील के निदेशकों ने नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच के फैसले को चुनौती दे रखा है। एस्सार स्टील का कहना है कि उसकी 54,389 करोड़ रुपये की बोली आर्सेलर मित्तल की बोली से अधिक है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के 100 फीसदी बकाये के भुगतान का खाका पेश किया गया है।
5. स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी एनसीएलएटी के खिलाफ याचिका दे रखी है। बैंक का कहना है कि एस्सार स्टील को दिए कर्ज का उसे मात्र 1.7 फीसद वापस मिल रहा है, जबकि अन्य फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को उनके बकाया रकम का 85 फीसद से अधिक हिस्सा मिल रहा है।
6. आर्सेलर मित्तल के प्रस्ताव में वित्तीय संस्थाओं को 41,987 करोड़ रुपये का बकाया चुकाए जाने का जिफ्र है, जबकि कुल बकाया 49,395 करोड़ रुपये है।

7. वहीं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कुल 4,976 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले 214 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अगर आर्सेलर मित्तल की योजना को मंजूरी दी जाती है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को मात्र 60 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि उसने 3,187 करोड़ रुपये का दावा कर रखा है।

इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में अब तक आए 12,000 मामले

इन्सॉल्वेंसी कानून लागू होने और नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) का गठन होने के बाद से अब तक इससे संबंधित 12,000 मामले दाखिल हो चुके हैं। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी कोड (आइबीसी) आखिरी विकल्प होना चाहिए और एनसीएलटी इन्सॉल्वेंसी मामलों को अत्यधिक तेजी से निपटा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ एनसीएलटी में दाखिल किए गए मामलों की संख्या और निस्तारित हो चुके मामलों की संख्या करीब समान है। इसका मतलब यह हुआ कि मामला लंबित नहीं है।

क्या है

1. आइबीसी के तहत टिब्यूनल की अनुमति के बाद ही मामले पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। देशभर में अलग-अलग जगहों पर एनसीएलटी की पीठ स्थापित की गई है। व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी के मामले में श्रीनिवास ने कहा कि इसके साथ अत्यधिक सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाना चाहिए।
2. व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसपर हमने सबसे पहले ध्यान दिया है। अभी करीब 77 लाख करोड़ रुपये का नॉन-फूड कर्ज बकाया है।
3. इसमें उद्योग की हिस्सेदारी करीब 26 लाख करोड़ रुपये की है। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 21 लाख करोड़ रुपये की है। इन दोनों सेगमेंट की कुल मिलाकर 48 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। यह बकाए नॉन-फूड कर्ज का 70 फीसद है। तीस फीसद बच गया है, जिसका अब निदान निकालना है।
4. श्रीनिवास के मुताबिक व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी के दो तरीके हैं। एक तरीका है पहले इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया चले और उसके बाद बैंकप्सी प्रक्रिया चले। दूसरा तरीका है नए सिरे से शुरुआत हो।

आतंकी फंडिंग पर भारत ने किया संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के स्थायी प्रतिनिधि सैय्यद प्रतिनिधि सैय्यद अकबरुद्दीन ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की आवश्यक भूमिका के लिए स्थापित वैश्विक मानकों के स्थापित करने का स्वागत किया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब आतंकी संगठनों को फंडिंग करने वाले देशों के खिलाफ अब संयुक्त राष्ट्र अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकेगा। 29 मार्च 2019 को सुरक्षा समिति (UNSC) में आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्य आतंकवादियों के लिए माफी मांग रहे हैं, वे अपनी कार्रवाई और निष्क्रियता को सही साबित करने के लिए कहीं न कहीं योगदान करते रहेंगे।

क्या है

1. अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के संदर्भ में यह भी कहा कि वो लगातार आतंक का समर्थन करते रहेंगे, उन्होंने कहा कि आतंकी हिंसा फैलाने के लिए नियमावली के नियमों का उल्लंघन कर अपने काम के लिए अब और भी ज्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं।
2. दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से जो भी देश आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, वही देश लगातार इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं।
3. UNSC में इस प्रस्ताव के दौरान पुलवामा हमले की भी चर्चा की गई। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को लेकर कड़ी निंदा की गई। इसके साथ ही अब भारत को आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिशों को कामयाबी मिल गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य सैय्यद स्थायी सदस्य सैय्यद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है।

4. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाने के बाद आतंकवाद पर लगाम लगाने की वैश्विक गति बढ़ रही है। अब, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादियों के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक संकल्प अपनाया है।

विज्ञान एवं तकनीकी

कॉसमॉस बैंक पर साइबर अटैक पर रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ओर से बनाए गए एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने बताया है कि पुणे के कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक पर साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ था। हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में संध लगाकर कथित तौर पर 28 देशों में एटीएम से 94 करोड़ रुपये निकाल लिए थे। इस पैनल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया की ओर से उल्लंघन का पता लगाने के लिए किया गया था। पैनल की रिपोर्ट कॉसमॉस बैंक पर साइबर हमले के लगभग सात महीने बाद आई है।

क्या है

1. रिपोर्ट में कहा गया है 'पैनल है, 'पैनल ने पाया है कि उत्तर कोरिया वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए साइबर हमलों का इस्तेमाल कर रहा है'। कॉसमॉस बैंक पर साइबर हमले की जांच कर रही पुणे पुलिस और महाराष्ट्र के साइबर सेल को अभी तक इस अपराध के मुख्य आरोपी को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है।
2. पुणे पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की ओर से पकड़े गए लोग अपराधियों और अपराधिक गिरोहों से जुड़े बिचौलिए हो सकते हैं।
3. ये विदेश में बैठे अपराधियों के इशारे पर भी अपराध करते हैं। पुणे पुलिस के डेप्युटी कमिश्नर संभाजी कदम ने हमारे सहयोगी इकॉनॉमिक टाइम्स को बताया, 'हू हमें बताया, 'हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के बारे में पता चला है लेकिन हमने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है' ।
4. अधिकारी के मुताबिक इसके लिए उस स्विच पर मालवेयर अटैक किया गया था जिसके जरिए वीजा और रूपे डेबिट कार्ड के पेमेंट गेटवे ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा, 'एटीएम कहा कहा, एटीएम ऑपरेट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम अब मालवेयर अटैक की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ट्रेल का पता लगाने में सफलता पाई है और कुछ देशों से जानकारी हासिल की है। हम ओरिजिनल सर्वर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ही हम यह कह सकेंगे कि सायबर हमला हमला किस किसी ग्रुप या देश ने किया था'। ने किया था।
5. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट से जांच में मदद मिलेगी। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स ने इस साइबर हमले के पीछे लजारस ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई थी। इस हैकर ग्रुप में उत्तर कोरिया से संबंधित लोग शामिल हैं।

साल का आखिरी सबसे बड़ा चांद

21 मार्च को वसंत पूर्णिमा की रात को आसमान का नजारा कुछ अलग होगा। पृथ्वी से करीब होने के कारण चांद रोजाना के मुकाबले आकार में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। 19 साल बाद वसंत के पहले दिन ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। इसके बाद ऐसा नजारा साल 2030 में दिखाई देगा। इसे upper worm moon नाम दिया गया है। यह साल का तीसरा और आखिरी uppermoon है। इससे पहले यह 21 जनवरी और 19 फरवरी को दिखाई दिया था।

क्या है Supermoon

1. चांद पृथ्वी के सबसे करीब आता है तो बड़े आकार में दिखता है। साथ इस स्थान पर उसे सूर्य मिलने वाली रोशनी से चमक बढ़ी हुई दिखती है।
2. इस दौरान पृथ्वी से उसकी दूरी करीब 3,60,000 किलोमीटर रहती है। वर्षों बाद यह खगोलीय घटना होती है। नचमतउववद से समुद्र में ऊंची लहरें भी उठती हैं।

क्या है

1. विश्व के कई देशों में इसका नजारा 20 मार्च की रात में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह 21 मार्च को नजर आएगा। हर नैनचमतउववद को अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
2. इससे पहले 21 जनवरी 2019 को साल का पहला upermoon दिखाई दिया था। इस दौरान चांद लाल तांबे के रंग जैसा नजर आया था। इस खगोलीय घटना को uper Blood Wolf Moon नाम दिया गया था। इसके बाद 19 फरवरी को साल का दूसरा upermoon दिखाई दिया था। इसे uper Snow Moon नाम दिया गया था।

घातक ट्यूबरक्लोसिस का मिला नया उपचार

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे टीबी का पूरी तरह इलाज हो सकेगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नोर्टे डेम के शोधकर्ताओं के अनुसार ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित कोशिका से निकले एक्सट्रासेल्युलर वेसिकल्स (ईवी) से टीबी को हराया जा सकता है। इससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। कोई भी कोशिका नष्ट होते समय अपने बाहर वेसिकल्स या पुटिकाएं उत्सर्जित करती है, जिन्हें ईवी कहा जाता है। टीबी से संक्रमित कोशिका से निकले ईवी में माइक्रोबैक्टीरिया ईवी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया) का आरएनए पाया जाता है।

क्या है

1. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बैक्टीरिया की कोशिका से निकले ईवी प्रतिरक्षा तंत्र में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका 'मैक्रोफेज' की अपेक्षा संक्रमण को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं।
2. अध्ययन के अनुसार टीबी के उपचार के लिए यदि एंटीबायोटिक के साथ ईवी का इस्तेमाल हो तो बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। चूहों पर इसका परीक्षण सफल रहा है।
3. टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को कई नामों से जाना जाता है जैसे इस क्षय रोग, तपेदिक, राजयक्ष्मा, दण्डाणु इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।
4. टीबी एक संक्रामक बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति में शारीरिक कमजोरी आ जाती है और इसके साथ ही उसे कई गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। टीबी सिर्फ फेफड़ों का ही रोग नहीं है, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी यह प्रभावित करता है।

टीबी संक्रमण के कारण

1. टीबी एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता जो संक्रमण से फैलता है। यदि कोई टीबी पीड़ित व्यक्ति आप के आसपास थूकता है, खांसता है, छींकता है, हंसता है या गाना भी गाता है तो संभावना है कि सांस के माध्यम से आप भी टीबी संक्रमणित हो जाएं। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति जो कम से कम दो सप्ताह से दवा सेवन कर रहा हो तो उससे इसके फैलने की संभावना कम हो जाती है।

टीबी के प्रकार

1. आमतौर पर टीबी तीन तरह का होता है। यह पूरे शरीर को संक्रमित करता है। टीबी के तीन प्रकार हैं- फुप्फुसीय टीबी, पेट का टीबी और हड्डी का टीबी। तीनों ही प्रकार के टीबी के कारण, पहचान और लक्षण भिन्न होते हैं। यही नहीं, तीनों प्रकार के टीबी का इलाज भी अलग-अलग तरह से किया जाता है।
2. फुप्फुसीय टीबी- इस प्रकार के टीबी को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। यह अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, तभी फुप्फुसीय टीबी के लक्षण उभरते हैं। फुप्फुसीय टीबी हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग-अलग होते हैं। सांस तेज चलना, सिरदर्द होना या नाड़ी तेज चलना आदि कुछ इसके लक्षण हैं।
3. पेट की टीबी- पेट में होने वाली टीबी की पहचान तो और भी मुश्किल होती है, क्योंकि पेट की टीबी पेट के अंदर ही तकलीफ देना शुरू करती है और जब तक इसके बारे में पता चलता है, तब तक पेट में गांठें पड़ चुकी होती हैं। दरअसल पेट की टीबी के दौरान मरीज को सामान्य रूप से होने वाली पेट की समस्याएं ही होती हैं जैसे बार-बार दस्त लगना, पेट में दर्द होना आदि।

4. **हड्डी की टीबी;** हड्डी टीबी- हड्डी में होने वाली टीबी की पहचान आसानी से की जा सकती है, क्योंकि हड्डी क्योंकि हड्डी में होने वाली टीबी के कारण हड्डियों कारण हड्डियों में घाव पड़ जाते हैं जोकि इलाज के बाद भी आराम से ठीक नहीं होते। शरीर में जगह-जगह फोड़े-फुंसियां होना भी हड्डी होना भी हड्डी की टीबी होने के लक्षण हैं। इसमें हड्डियां हैं। इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
5. टीबी से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़िया रखें। न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाकर प्रोटीन डाइट (सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, पनीर आदि) भरपूर मात्रा में लें। अगर आपकी इम्युनिटी कमजोर है तो टीबी के बैक्टीरिया के एक्टिव होने की आशंका ज्यादा रहती है। असल में कई बार टीबी का बैक्टीरिया शरीर में तो होता है, लेकिन अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह एक्टिव नहीं हो पाता और टीबी नहीं होती।

डायनासॉर के प्राचीनतम अंडे खोलेंगे उनकी उत्पत्ति के राज

विश्व में डायनासॉर के सबसे पुराने ज्ञात अंडों से वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय जीव की उत्पत्ति के बारे में नई सूचनाएं निकाली हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मिसिसॉगा के अनुसंधानकर्ताओं ने अर्जेंटीना, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए स्थानों पर इन अंडों एवं अंडे के छिलकों के जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन किया।

क्या है

1. अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि 19.5 करोड़ साल पुराने ये अंडे जीवाश्म रेकॉर्ड में ज्ञात सबसे प्राचीन अंडे हैं। ये सभी अंडे सॉरोपोड्स ने दिए थे। सॉरोपोड्स चार से आठ मीटर लंबे तथा लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव थे और अपने समय के सबसे आम एवं दूर-दूर तक पाए जाने वाले डायनासॉर थे।
2. टोरंटो यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट रीस्ज ने कहा, 'जीवाश्म कहा, रजीवाश्म रिकॉर्ड में रेंगने वाले एवं स्तनपायी परभक्षियों के 31.6 करोड़ साल पुराने कंकाल मौजूद हैं, लेकिन 12 करोड़ साल बाद तक भी उनके अंडों और अंडों के खोलों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं।' 'रीस्ज। जानते हैं। रीस्ज ने एक बयान में कहा, 'यह में कहा, शयह बड़ा रहस्य है कि ये अंडे अचानक से इस समय नजर आए हैं और इससे पहले नहीं दिखें।' दिखे थे।
3. बेल्जियम की घंट यूनिवर्सिटी के एक अनुसंधानकर्ता कोइन स्टेन के मुताबिक ये अंडे डायनासॉरों में प्रजनन प्रक्रिया के क्रमिक विकास का पता लगाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं।

नासा के लेजर उपकरणों लेकर जाएगा चंद्रयान-2

भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान-दो अगले महीने प्रक्षेपित होने वाला है और वह नासा के लेजर उपकरणों को अपने साथ चंद्रमा तक लेकर जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा तक की दूरी का सटीक माप लेने में मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते अमेरिका के टेक्सास में हुए चंद्र एवं ग्रह विज्ञान सम्मेलन के दौरान नासा ने इस बात की पुष्टि की थी तैयार चंद्रयान दो और इजराइली यान बेरेशीट, दोनों नासा के स्वामित्व वाले लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरै को साथ लेकर जाएंगे।

क्या है

1. स्पेस डॉट कॉम ने नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय में ग्रह विज्ञान विभाग की कार्यवाहक निदेशक लोरी ग्लेज के हवाले से कहा, "हम पूरी सतह को जितना संभव हो उतने अधिक लेजर रिफ्लेक्टर से भर देने का प्रयास कर रहे हैं।"
2. रेट्रोफ्लेक्टर ऐसे परिष्कृत शीशे होते हैं जो धरती से भेजे गए लेजर रोशनी संकेतों को प्रतिबिंबित करते हैं।
3. ये सिग्नल यान की मौजूदगी का सटीक तरीके से पता लगाने में मदद कर सकते हैं जिसका प्रयोग वैज्ञानिक धरती से चंद्रमा की दूरी का सटीक आकलन करने के लिए कर सकते हैं।

विविध

मनोहर पर्रिकर का निधन

गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। चार बार गोवा के सीएम रहे 63 वर्षीय पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। 17 मार्च 2019 को सुबह 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।

क्या है

1. वह बीते एक साल से बीमारी से पूरी जीवटता के साथ संघर्ष कर रहे थे। पार्टी लाइन से ऊपर वह सम्मानित नेता थे और गोवा के सबसे अच्छे लोगों में से थे।
2. **कैंसर से गंभीर तौर पर जूझने के बावजूद** वह बीते कई महीनों से सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। नाक में ड्रिप लगाए उनकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।
3. गोवा में बीजेपी और राजनीति के एक मजबूत स्तंभ रहे मनोहर पर्रिकर आईआईटी से पढ़े थे। देश के पढ़े-लिखे और सादगी से जीवन जीने वाले नेता के तौर पर उनकी खास पहचान थी।
4. गौरतलब है कि **फरवरी 2018 में पर्रिकर को पैक्रियाटिक कैंसर की पहचान** हुई थी। वह गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यू यॉर्क के अस्पतालों में इलाज करा चुके हैं।
5. जिन दिनों वह बेहद बीमार थे, तब वह राज्य की विधानसभा में 2019-20 का बजट पेश करने आए थे। इस दौरान उन्होंने बेहद आत्मविश्वास से कहा था, 'मैं था, मैं जोश में भी हूँ और होश में भी हूँ'। भी हूँ।

वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे चिनूक हेलिकॉप्टर

भारतीय वायुसेना की ताकत में 25 मार्च 2019 को इजाफा होने जा रहा है। **अमेरिकी कंपनी बोइंग** द्वारा बनाए गए चिनूक सीएच-47आइ हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में 25 मार्च को चंडीगढ़ में शामिल किया जाना तय हुआ है। इस मौके पर एक इंडक्शन समारोह का आयोजन वायुसेना करने जा रहा है। **सीएच-47 चिनूक एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर** है, जो भारतीय वायुसेना को बेजोड़ सामरिक महत्व की हेवी लिफ्ट क्षमता प्रदान करेगा। यह मानवीय सहायता और लड़ाकू भूमिका में काम आएगा।

क्या है

1. **उंचाई वाले इलाकों में भारी वजन के सैनिक साज सामान के परिवहन में इस हेलीकॉप्टर की अहम भूमिका** होगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तक **रूसी मूल के भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टर** ही रहे हैं।
2. लेकिन पहली बार वायुसेना को अमेरिका निर्मित हेलीकॉप्टर मिलेंगे। चिनूक बहुउद्देशीय, वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन ढोने में किया जाता है। **इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है।** राहत सामग्री पहुंचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
3. इसमें पूरी तरह एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा इसमें कामन एविएशन आर्किटेक्चर काकपिट और एडवांस्ड काकपिट प्रबंध विशेषताएं हैं। इस हेलीकॉप्टर का दुनिया के कई भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में काफी क्षमता से संचालन होता रहा है।
4. चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के अलावा कई देशों की सेनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। खासकर भारतीय क्षेत्र में इस हेलीकॉप्टर की विशेष उपयोगिता होगी।
5. भारतीय वायुसेना ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को हासिल करने का आर्डर दिया था जिसमें से पहला चिनूक हेलीकॉप्टर इस साल फरवरी में आया था। सितंबर 2015 में भारत के बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया गया था।

- अगस्त 2017 में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 4168 करोड़ रुपये की लागत से छह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर अन्य हथियार प्रणाली खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की थी।

माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान

माउंट मकालू (8485 मीटर) के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को 26 मार्च, 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोही दल में पांच अधिकारी, दो जेसीओ और 11 ओआर शामिल हैं। 8000 मीटर से ऊंची सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों पर चढ़ने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना मार्च-मई 2019 में माउंट मकालू के लिए अपना पहला अभियान शुरू कर रही है।

क्या है

- माउंट मकालू को सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है और मौसम की दुरुह परिस्थितियों और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है।
- यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों की तकनीकी सूझबूझ, मानसिक और शारीरिक साहस तथा माउंट मकालू के शिखर तक पहुंचने के उनके संकल्प की परीक्षा लेगी।
- इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इस दल को पिछले छह महीनों से कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
- इस अभियान की तैयारियों के तहत इस दल ने माउंट कामेट का सफल अभियान किया और 2018 में माउंट भनौती का आरोहण करने सहित शीतकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- यह दल इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नई दिल्ली से रवाना होगा और माउंट मकालू की चोटी के शिखर तक पहुंचने के रास्ते में 6 शिविर स्थापित किये जायेंगे।

विश्वविद्यालयों में चालू रहेंगे शोध

विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध और शैक्षणिक सुधार से जुड़े कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय व कालेज स्तर पर संचालित ऐसे करीब 30 कार्यक्रमों को 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल इन कार्यक्रमों के संचालन की अवधि 31 मार्च 2019 को खत्म हो रही थी। इससे पहले इन कार्यक्रमों को 2017 में भी इसी तरह विस्तार दिया गया था।

यूजीसी फिलहाल विश्वविद्यालय व कालेजों में इन कार्यक्रमों के जरिए जो मुहिम छेड़ रखी है, उनमें महिलाओं के लिए पर्याप्त छात्रावास का निर्माण सहित ऑन लाइन कोर्स का संचालन और शोध को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं।

क्या है

- यूजीसी इसके लिए विश्वविद्यालय और कालेजों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है। ऐसे में इनके संचालन के लिए यूजीसी की मंजूरी काफी अहम होती है। फिलहाल यूजीसी ने विवि और कालेजों में पहले से संचालित हो रहे सभी 30 कार्यक्रमों को 31 मार्च 2020 तक जारी रखने का आदेश भी जारी कर दिया है।
- यूजीसी के मुताबिक विवि और कालेज स्तर पर संचालित होने वाले इन कार्यक्रमों की एक निश्चित समय सीमा में समीक्षा भी की जाती है। इसके तहत किन कार्यक्रमों को आगे जारी रखना या बंद करना जैसे फैसले भी लिए जाते हैं।
- फिलहाल मार्च 2020 तक जारी रखने के फैसले में पहले से संचालित कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले की तरह सभी 30 कार्यक्रमों को जारी रखा गया है।
- देश भर में मौजूदा समय में करीब नौ सौ विश्वविद्यालय और पचास हजार से ज्यादा कालेज संचालित हैं। इनमें निजी विश्वविद्यालय और स्वायत्त कालेज भी शामिल हैं।
- विवि और कालेजों में फिलहाल यूजीसी की मदद से जिन बड़े कार्यक्रमों का संचालन होता है, उनमें पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम, फेलोशिप स्कीम, बड़े शोध कार्यक्रम, नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क, एरिया स्टडी प्रोग्राम,

यूजीसी चेयर इन यूनिवर्सिटी, एससी,एसटी और ओबीसी सहित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग स्कीम आदि शामिल है।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड

सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। वहीं, इस लिस्ट में नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 59वें नंबर पर रहा है। इस लिस्ट को यूके की कंसल्टेंसी फर्म स्काईट्रैक्स ने जारी किया जो कि एयरलाइन और एयरपोर्ट की रिव्यू और रैंकिंग साइट भी चलाती है, जिसमें 100 एयरपोर्ट्स शामिल हैं। लंदन में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2019 में इस अवार्ड को दिया गया। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में वैश्विक स्तर पर एयरपोर्ट ग्राहक अपनी सुविधा के आधार पर वोट देते हैं।

क्या है

1. सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अपनी हाइटेक फैसिलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अपने रूप टॉप स्विमिंग पूल, 24 घंटे चलने वाले दो मूवी थिएटर्स और शॉपिंग स्पॉट्स के चलते पूरी दुनिया में फेमस है।
2. अब इस एयरपोर्ट में एक नई खूबी के तौर पर दुनिया का सबसे लंबा इनडोर वॉटरफॉल भी अप्रैल तक शामिल हो जाएगा। यात्रियों के लिए चांगी एयरपोर्ट पर अलग-अलग तरह की हाइटेक फैसिलिटी मौजूद हैं। क्राउन प्लाजा होटल और उसकी सुविधाओं की वजह से इस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट होटल का अवार्ड भी मिला है।
3. दुनिया के शानदार एयरपोर्ट में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (हनेडा) इस साल दूसरे नंबर पर है, जो कि पिछले साल तीसरे नंबर पर था। इस एयरपोर्ट को दुनिया के बेस्ट घरेलू एयरपोर्ट और सबसे साफ एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है।
4. साउथ कोरिया का इंचेऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर आ गया है जो कि पिछले साल दूसरे नंबर पर था। इसको दुनिया के बेस्ट ट्रांजिट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है।
5. भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 59वें नंबर पर आया है, जो कि पिछले साल 66वें नंबर पर था।
6. इस लिस्ट में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस साल 64वें नंबर पर आया, जो पिछले साल 63वें नंबर पर था।
7. राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66वें नंबर पर आया, जिसको 10 पायदान की बढ़त मिली है। बंगलुरु का कम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66वें नंबर पर आया जो कि पिछले साल से 5 पायदान नीचे है।

खास है 29 मार्च का दिन

आजादी की पहली जंग यानि 1857 के विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। आजादी के लिए भारत की इस पहली अंगड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे ही एक वीर थे मंगल पांडे। मंगल पांडे से जुड़ी किस्से कहानियां हम सबने बचपन से ही सुनी हैं। 29 मार्च वही दिन है, जिस दिन मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूँका था। वह आज का ही दिन था जब बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेन्ट्री के सैनिक मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड में दो अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया। इसके बाद 7 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी।

क्या है

1. यह भी गौर करने वाली बात है कि स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडेय जैसे भारत मां के वीर सपूत को फांसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद कलकाता से चार जल्लादों को बुलाकर मंगल पांडे को फांसी दी गई।
2. मंगल पांडे जब 22 साल के थे तभी वो ईस्ट इंडिया कम्पनी से जुड़ गए थे। मंगल पांडे शुरु से ही फौज में जाने को लेकर हमेशा उत्साहित रहते थे। ईस्ट इंडिया से जुड़ने के बाद सबसे पहले उनकी नियुक्ति अकबरपुर के एक ब्रिगेड में हुई थी।
3. अंग्रेजों के बीच रह कर धीरे-धीरे उनका मन मिलेट्री सर्विस से भर गया। सर्विस के दौरान एक घटना क्रम ने उनका जीवन बदल दिया। भारत में तब एक नए प्रकार की राइफल लांच हुई थी।

4. राइफल का नाम एनफील्ड था। राइफल का उपयोग आर्मी में किया जाने लगा था। राइफल के कार्टिज पर जानवरों की चर्बी से ग्रीज लगे होने की अफवाह उड़ी थी। कार्टिज में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी।
5. **सैनिकों को राइफल के ग्रीज लगी कार्टिज को मुंह से छीलकर** हटाना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को लगने लगा की अंग्रेज उनके साथ धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तभी मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया की सर्विस से इस्तीफा देकर अंग्रेजों से बदला लेने की सोची, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में खुलकर सामने आ गए।
6. आज का दिन भारत के लिए एक और ऐतिहासिक वजह से महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक घटना भी अंग्रेजों से जुड़ी है। साल 1859 में वो 29 मार्च का ही दिन था जब अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को देश निकाला दिया था। उन्हें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भागीदारी का दोषी पाया गया और अंग्रेज सरकार ने उन्हें रंगून भेज दिया। बाद में रंगून में ही उनकी मौत हुई थी।
7. 1857 में **प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर** को हार का सामना करना पड़। जिसके बाद 17 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर मकेंजी नाम के समुद्री जहाज से रंगून भेज दिया गया।
8. इस जहाज में शाही खानदान के 35 लोग सवार थे। उस दौरान कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून जो वर्तमान में यंगून है के इंचार्ज थे। 17 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर को एक गैराज कैद किया गया जहां से वो 7 नवंबर 1862 में अपनी चार साल की कैद के बाद जिंदगी को अलविदा कहते हुए आजाद हो गए। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर गजल इसी गैराज में लिखी थी।

कोरिया ने भारत को हराया

सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा दिया। दोनों टीमों फुलटाइम तक 1-1 की बराबरी थी। पेनल्टी शूटआउट में **कोरिया की टीम** 4-2 से जीत गई। इस जीत के साथ ही उसने नौ साल बाद इस खिताब को अपने नाम किया। 2010 में वह भारत के साथ संयुक्त विजेता बना था। वहीं, इस हार से भारत का छठी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। टीम इंडिया 1985, 1991, 1995, 2009 और 2010 में चौम्पियन बनी थी।

क्या है

1. भारत टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंचा था। **राउंड रॉबिन लीग राउंड में कोरिया के साथ** उसका मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था।
2. भारत ने नौवें मिनट में ही सिमरनजीत सिंह के गोल से बढ़त बना ली थी। कोरिया ने 47वें मिनट में गोल कर मैच को बराबर कर दिया।
3. मैच के आखिरी 13 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। पेनल्टी शूट आउट में भारत के सुमित और सुमित कुमार ने मौके गंवाए। बीरेंद्र लाकड़ा और वरुण कुमार ही गेंद को गोलपोस्ट में डाल सके।
4. दूसरी ओर, कोरिया की तरफ से चार खिलाड़ियों ने गोल किए। सिर्फ किहून किम गेंद को गोलपोस्ट में नहीं डाल सके।